



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, ३० अप्रैल, १९९८/१० बंशाख, १९२०

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-२, २९ अप्रैल, १९९८

संख्या एल० एन० आर० (राजभाषा) (बी) १६-१/९८.—“दि हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एण्ड गुड्ज टैक्सेशन (अमैन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९८८ (१९८८ का १०)” के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख २७ अप्रैल, १९९८ के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में

प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

आदेश द्वारा, *

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 1988

(1988 का 10)

(27 मई, 1988 को राज्यपाल द्वारा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान संक्षिप्त नाम । पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 1988 है ।

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में — धारा 2 का संशोधन ।

(i) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (घ घ) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(घ घ) “छोटी बस” से ड्राइवर या कन्डक्टर को अपवर्जित करते हुए, तीस से अनधिक यात्रियों के वहन धारिता वाली मंजिली गाड़ी (Stage Carriage) अभिप्रेत है ;”;

(ii) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड (च) रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(च) “मोटर गाड़ी” से सार्वजनिक सेवा की गाड़ी या सार्वजनिक वाहन या वैयक्तिक वाहन अथवा ठेला, जब वह ऐसी गाड़ी के साथ लगा हो, अभिप्रेत है और मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के उल्लंघन में यात्रियों और सामान के वहन या भाड़ा या पारिश्रमिक दोनों के लिए प्रयोग की गई कोई भी गाड़ी इसके अन्तर्गत है ;”;

(iii) खण्ड (ज) में “सार्वजनिक सेवा की गाड़ी” शब्दों के स्थान पर, “मोटर गाड़ी” शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा (2-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— धारा 3 का संशोधन ।

“(2-क) जहां कोई मोटर गाड़ी, सार्वजनिक सेवा गाड़ी से भिन्न है, मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के उपबन्धों के उल्लंघन में भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चलती है, तो ऐसी गाड़ी का स्वामी किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उस अधिनियम के अधीन की जाती है या की जा सकती, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर कर

या किराया और माल भाड़े की ऐसी रकम जो विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अवधारित की जाए, संदत्त करने के लिए दायी होगा।”

नई धारा 7-क 4. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा 7-क अन्तः-
का अन्तः- स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
स्थापन।

“7-क. कराधायक प्राधिकारी को सहायता देना.—इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुपालन में, जब अपेक्षित हो, आयुक्त और इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने को नियुक्त सभी अन्य व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सभी पुलिस अधिकारी आबद्ध होंगे और, उस प्रयोजन के लिए, उन्हें वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उन्हें अपने साधारण पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में प्राप्त हैं।”

धारा 8 का 5. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 को उप-धारा (1) के रूप में संशोधन। पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, मोटर गाड़ी के स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर, जिसके साथ बीस रुपए की फीस भी होगी, जो मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जो उस अधिनियम की धारा 62 के अधीन दिए गए अस्थायी अनुज्ञा पत्र पर चार मास से अनधिक अवधि के लिए और उस अधिनियम के अधीन संदेय कर और अधिभार के अग्रिम संदाय पर चलाई जाती है, तो निर्धारण प्राधिकारी इस धारा के अधीन विधिमन्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकगा।”

धारा 9 का 6. मूल अधिनियम की धारा 9 में—
संशोधन।

(क) उप-धारा (1) में “एक रुपया” शब्दों के स्थान पर “दस रुपए” शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) उप-धारा (4) में “विहित रीति से” शब्दों के पश्चात् “कर राशि के डेढ़ गुना” शब्दों के स्थान पर, “न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन इस प्रकार निर्धारित कर और अधिभार राशि के पांच गुना” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10 का 7. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, प्रतिस्थापन। अर्थात्:—

“10. छूट.—जहां राष्ट्रीय या लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहां राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकगी।”

8. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित धारा 13 का उप-धाराएं (4), (5) और (6) जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:— संशोधन ।

“(4) किसी मोटर गाड़ी के स्वामी के सभी लेखे, रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य बहियां सभी युक्तियुक्त समयों पर आयुक्त या किसी अन्य विहित प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी और आयुक्त या ऐसा प्राधिकारी ऐसे किसी या सभी लेखों, रजिस्ट्रों, दस्तावेजों तथा बहियों पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकेगा।

(5) यदि आयुक्त या विहित प्राधिकारी के पास यह सन्देह करने का कारण हो कि किसी मोटर गाड़ी का कोई स्वामी इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय का अपवंचन करने का प्रयास करता है, तो आयुक्त या ऐसा प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे स्वामी के ऐसे लेखे, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य बहियों को जैसे आवश्यक हों, अभिगृहीत कर सकेगा और उसके लिए रसीद देगा तथा उसे केवल तब तक ही रख रखेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन उसके परीक्षण के लिए या किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ।

(6) उप-धारा (4) और (5) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, आयुक्त या विहित प्राधिकारी मोटर गाड़ी के किसी स्वामी के किसी कारवार क स्थान में प्रवेश कर सकेगा ।”

9. मूल अधिनियम की धारा 13-क की उप-धारा (1) में “आबकारी और कराधान अधिकारी” शब्दों के पूर्व “यथास्थिति, सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त या” शब्द जोड़े जाएंगे । धारा 13-क का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 13-क के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 13-कक अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 13-कक का अन्तःस्थापन ।

“13-कक. गाड़ी को रोकने की शक्ति.—धारा 13 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मोटर गाड़ी द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर या शास्ति, यदि कोई हो, का संदाय किए बिना, हिमाचल प्रदेश राज्य में या बीच से यात्रियों और सामान का वहन किया जा रहा है या जहां स्वामी कर या शास्ति, यदि कोई हो, संदत्त करने से इन्कार करता है अथवा उसके संदाय के बारे में कोई सबूत पेश करने में असफल रहता है, गाड़ी को रोक सकेगा और इस प्रयोजन के लिए कोई पग जो गाड़ी की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित समझे, उठाएगा या उठाएगा :

परन्तु जैसे ही कर या शास्ति, यदि कोई हो, संदत्त कर दी जाती है तो गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा ।”

11. मूल अधिनियम की धारा 14-क में—

धारा 14-क का संशोधन ।

(क) उप-धारा (1) में आए “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “पांच हजार रुपए” तथा “से अनधिक” शब्दों के पश्चात् “किन्तु एक सौ रुपए से कम नहीं” शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी किन्तु जो आबकारी और कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।”

धारा 16-क 12. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित का संशोधन। नई उप-धारा (1-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“(1-क) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन के साथ अधिरोपित, यथास्थिति, कर या शास्ति, यदि कोई हो, या दोनों के संदाय का समाधानप्रद सबूत नहीं है :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि स्वामी निर्धारित कर या अधिभार या अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, अथवा दोनों संदत्त करने में असमर्थ है, तो वह, कारणों को अभिलिखित करते हुए, कर और अधिभार या शास्ति अथवा दोनों दिए बिना या ऐसे कर और अधिभार या शास्ति या दोनों के आंशिक संदाय के पश्चात्, आवेदन ग्रहण कर सकेगा।”

धारा 22 का संशोधन। 13. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (कक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(कक). वह रीति, जिसमें धारा 3 की उप-धारा (2-क) के अधीन कर और अधिभार के संदाय के प्रयोजन के लिए किराया और भाड़े की रकम अवधारित की जाएगी ;”।